हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

16 मार्च, 1981

खण्ड 1, अंक 6

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 16 मार्च 1981

पृश्ठ संख्या

औचित्य प्र न – वित्त मंत्री की अनुपस्थिति सम्बंधी	(6) 1
वर्श 1981–82 का बजट पे ा करना	(6) 3

हरियाणा विधानसभा

सोमवार, 1 मार्च 1981

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधानसभा हाल, विधान भवन, सैक्टर –1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

औचित्य प्र न –

वित्त मंत्री की अनुपस्थिति संबंधी

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब फाईनैंस मिनिस्टर वर्श 1981–82 के बजट ऐस्टिमेटस पे ा करेंगे।

विपक्ष की ओर से आवाजें: अध्यक्ष महोदय, मैं पे ा कर देता हूं। (ाोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं पे ा कर देता हूं। (ाोर)

Ch. Ram Lal Wadhwa: Budget can not be presented by the Chief Minister. (Interruptions) Only the Finance Minister can do it.

Dr. Mangal Sein: It has never been presented by the Chief Minister. (Interruptions).

Ch. Ram Lal Wadhwa: It is unprecedented that the Finance Minister is not present at the time of presenting the Budget. (Noise)

श्री वीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, हाउस ऐडजर्न कर दीजिए। (ाोर)

Mr. Speaker: Please sit down. (Noise) As far as the Government business is concerned, any Minister of the Government can conduct the same and specifically I would say that if the Finance Minister happens to be indisposed or is otherwise unable to come due to unavoidable circumstances, any other Minister can conduct the business on his behalf.

Dr. Mangal Sein: He is quite hale and heartly, Sir. (Interruptions).

Ch. Ram Lal Wadhwa: Have you been informed about his indispoistion, Sir. (Interruptions).

Mr. Speaker: I am not informed but there can be situations in which a person may not be able to come. (Interruptions).

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, हाउस को एडजर्न कर दो। (ाोर)

श्री अध्यक्षः पांच मिनट के लिए किसी को कहीं जाना भी पड सकता हैं (ाोर)

चौधरी गंगा रामः हाउस आज ऐडजर्न हो जाना चाहिए। (ाोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को इतना मालूम होना चाहिए कि कोई भी मिनिस्टर सरकारी बिल या बजट हाउस में पे ा कर सकता है। (विघ्न एवं भाोर)

Dr. Mangal Sein: Speaker Sahib, on a point of order. I want to draw you attention to Rule 188 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly which is regarding the presentation of Budget. This rule reads as under :

"T'he Annual Financial Statement or the Statement of the Estimated Receipts and Expenditure of the Government of the State in respect of every financial year (hereinafter referred to as "The Budget" shall be presneted to the Assembly on such day as the Governor may appoint."

स्पीकर साहब, बजट प्रेजैंट करने के लिए आज का दिन अप्वायंटिड था और आज के एजेन्डे में भी लिखा हुआ है कि फाईनैंस मिनिस्टर साहब बजट पे ा करेंगे।

इस समय वित्त मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद) सदन में आ गए।

सत्ताधारी दल की ओर से आवाजेंः स्पीकर साहब, वित्त मंत्री जी आ गए हैं।

डा0 मंगल सैन: स्पीकर साहब, इतने इम्पोर्टेंट ओकेजन पर भी अगर फाईनैंस मिनिस्टर साहब हाउस में हाजिर नहीं होते तो he is unfit to be a Finance Minister. (Noise)

Ch. Ram Lal Wadhwa: It is a contempt of the House, Sir. (Noise)

Mr. Speaker: I had referred that the Finance Minister will present the Budget. Now, the definition of the Finance Minister, according to rules, runs as follows :-

"Finance Minister" means the Minister to whom the business of Finace has been allotted by the Governor and includes any Minister.

Howerver, I have noted the feelings of my hon. friends and I would request the Finance Minister to be in time in future, otherwise he might miss the boat on some other occasion.

Finance Minister (Ch. Khursid Ahmad): Mr. Speaker, Sir, I am sorry that I am a bit late. (Noise)

Dr. Mangal Sein: He is late by five minutes. Sir, (Noise)

Shri Baldev Tayal: On a point of order, Sir. For the presentation of the Budget, a specific time is fixed and you would be pleased to note that it was 2.00 p.m. Atleast the Finance Minister should have that much of grace as to express his regrets to the House and to you, Sir, for not presenting the Budget at the appointed hour.

Ch. Khurshid Ahmed: I have already expressed my regrets.

Mr. Speaker: I am convinced that there was not malafide intention on the part of the Finance Minister and I also realise that the human body being what it is, 5 minutes late on the part of this side or that side doen not matter much. Certain requirements of the human body can be such that they cannot wait for either the Finance Minister or anybody else.

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, ये बजट की इम्पोर्टेंस नहीं समझते। (ाोर) इनको समय से आना चाहिए था। (विघ्न)

Shri Baldev Tayal: On a point of order, Sir. I want to submit that the Finance Minister should express regrets for coming late.

Mr. Speaker: Tayal Sahib. Please sit down. He has already expressed his regrets for it. You probaly missed to hear it.

Shri Baldev Tayal: Sir, I have not heard it.

Mr. Speaker: I have heard that.

Shri Baldev Tayal: That is all right, Sir.

वर्श 1981–82 का बजट पे ा करना

वित्त मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमाय सदन के सामने वर्श 1981–82 के बजट अनुमान पे ा करने के लिए खड़ा हुआ हू। ये अनेक प्रकार के मुख्य भीर्श, लघु भीर्श, उप ीर्श और विनियोजनों की मूल इकाइयों में विभाजित, बेअंत आकंडों का यह रूखा सूखा दिखने वाला दस्तावेज वास्तव में अपने अंदर सरकार के कार्यक्रम और उसकी उपलब्धियों की गाथा समोये हुये हैं तथा इससे यह भी पता चलता है कि हम राज्य के विकास को क्या दि ाा देना चाहते हैं। ज्यों ही विवरण आपके सामने आयेगा यह बात स्पश्ट होती जायेगी कि जहां हमारी विकास गतिविधियों की दि ाा बदल रही है या उनमें तबदीली ला दी गई हैं, वहां दूसरे क्षेत्रों में भाुरूआत भी हो रही है। हम इसमें किस सीमा तक सफल होते हैं, यह बात कई एक अन्य आंतरिक एवं बाह्य कारणों पर निर्भर करती है। जहां साधनों की उपलभ्यता हमारे कार्यक्रमों की सीमा को निर्धारित करती हैं वहां बाह्य परिवे ा का महत्व भी कम नहीं है जैसे कि राश्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, प्र ाासकीय ढांचें की सुदृढता तथा राज्य की जनता का, हमारे सांझे उद्दे यों में पूर्ण वि वास रखते हुए प्रगति के मार्ग पर तीव्रता से अग्रसर होने का संकल्प। इसी कारण मैं पूर्व परिपाटी से थोडा सा हट कर इस सदन का ध्यान पहले सरकार के उद्दे यों और कार्यक्रमों की और दिलाना चाहूंगा और राज्य की कुल वित्तीय स्थिति सम्बंधी चर्चा बाद में करूंगा।

राश्ट्रीय आर्थिक स्थिति

वर्तमान बजअ कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया हैं इनमें सर्वप्रथम तो यही हे कि केन्द्र में एक नई सरकार के सतारूढ होने के एक वर्श से कुछ समय के बाद यह बजट प्रस्तुत किया जा रहा है और यह भी महत्वपूर्ण है कि इस अवधि में राश्ट्र की एक नई पंचवर्शीय योजना तैयार हो चुकी है, जिसमें राज्य की नई योजना भी भाामिल है। एक नई योजना राश्ट्र के लोगों द्वारा विभिन्न गतिविधियों के लिये दिये गये एक नये एवं स्पश्ट फरमान पर आधारित है। जनता द्वारा ऐसा स्पश्ट और नि चयात्मक फरमान देने की नितांत आव यकता इस कारण भी थी कि इन दिनों को जो आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, वह एक गंभीर चिन्ता का विशय था। मुद्रास्फीति (inflation) नई ऊंचाई को छू चली थी। उत्पादन राश्ट्र की जरूरतों की रफ्तार के मुताबिक बढना बंद हो गया था। उत्पादक प्रयासों में बडी भारी हानि हो रही थी और बात बिना बात के लिए आंदोलनों का सहारा लेना एक आम बात थी। वर्श 1979–80 में सकल राश्ट्रीय उत्पादन पिछले वर्शों से 4.5% कम हुआ, जबकि 1980–81 में 6.5% की वृद्धि से इस गिरती हुई स्थिति में परिवर्तन की संभावना हुई है। इसी प्रकार वर्श 1979–80 के दौरान राश्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय भी पिछले वर्शों से कम हो गई थी, मुद्राफीति की दर जून 1980 के अंत तक 23% (वार्शिक दर) तक पहुंच गई थी, इसके अतिरिक्त, दे ा और राज्य दोनों के सामने अन्य बहुत सी मूलभूत समस्यायें विद्यमान हैं। उत्पादन क्षमता, वि ोशकर कृशि उत्पादन यथा खाद्यान्न, दालें, तिलहन, कपास, गन्ने एवं निर्मित वस्तुयें यथा

कपडा, स्टील, सीमेंट आदि पर जनसंख्या की अविराम वृद्धि से उत्पन्न बोझ की समस्या भी हैं। जनसंख्या के 2% की वार्शिक वृद्धि के कारण राश्ट्रीय उत्पाद में 2% वार्शिक वृद्धि होने पर भी प्रति व्यक्ति आय का स्तर ज्यों का त्यों बना रहता है। इतना ही नहीं, हमारे वृद्धि दर का सामान्य वितरण ऐसा है कि राश्ट्रीय उत्पाद में 2% की वृद्धि के बावजून भी अधिकां ा जनता में खु ाहाली की बजाय गरीबी बढती है। इसका कारण यह है कि अधिकतर जनसंख्या अपनी रोजी के लिये पूरी तरह अथवा अधिकां ा रूप से जमीन पर ही निर्भर है और हमारी अर्थव्यवस्था में कृशि ही ऐसा क्षेत्र है जो कि बार बार सूखा एवं बाढ का सामना करता है, जहां भूमि जोत का निरंतर विभाजन होता जाता है, आव यक कृशि निवे ाों का मूल्य बढता जाता है तथा बचत की कमी एवं पूंजी विन्यास व ऋणों के अभाव के कारण उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती और जो भी थोडी वृद्धि हो पाती है वह छोटी बडी जोतों के मालिकों में असमान अनुपात से बढती है। इस प्रकार हमारी कृशि व्यवस्था में दायमी गरीबी ही नहीं बल्कि निरंतर बढती हुई दरिद्रता के बीज विद्यमान हैं अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में अधिक कमाई को बांटने के लिये उपलब्ध प्रणालियां भी एक सीमा तक ही कारगर हैं, क्योंकि उत्तरोत्तर प्रत्यक्ष कराधान की नीति सम्पत्ति के पुनर्वितरण में किसी सीमा तक ही सफल होती हैं यदि छोटे और सीमान्त किसान की हालत और भी खराब है। योजना के दस्तावेज से व्यक्त होता है कि वर्श 1977–78 में राश्ट्र की 48% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह कर रही थी।

हमारे अपने अनुमान के अनुसार वर्श 1978–79 में हरियाणा की 36% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी।

इतनी गम्भीर समस्याओं पर काबू पाना कोई आसान काम नहीं है। भाायद उसके लिये उठाये जाने वाले पगों कें संबंध में भी एक मत होना कठिन है। गरीबी पर काबू पाने के लिये अनिवार्यतः दो मूलभूत बातों की जरूरत है; इनमें पहली यह है कि खपत में आने वाले सामान और सेवाओं में इजाफा किया जाए और दूसरी यह कि सामान और सेवाएं गरीबों को उपलब्ध हों। इस प्रकार हमारे सामने उत्पादन को बढाने और उसका सही प्रकार से पुनर्वितरण सुनि ि चत करने की दोनों आव यकताएं हैं। इनमें पहली समस्या के हल के लिये भौतिक और वित्तीय निवे ाों को एकत्रित करने की अर्थात पंजीविन्यास की आव यकता होगी, जिसके वित्तीय भाग की उपलब्धि उत्तरोत्तर बचतों से एवं सभी द्वारा यथासंभव मौजूदा खपत को घटाने पर ही हो सकती हैं। दूसरी समस्या का हल मूल्य नियंत्रण और वितरण पद्धति के कु ाल संचालन तथा रोजगार और खासतौर पर स्वयं रोजगार के अवसर जुटाने पर ही हो सकेगा। इसके साथ साथ निर्मित पूंजी को उत्पादन ाील काम धंधों में नियोजित करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि इसका कुछ भाग सामाजिक और सामुदायिक कल्याणकारी सेवाओं के लिये निर्धारित किया जाये, भले ही इस प्रकार की सेवाओं के लाभ को नकदी की भाक्ल में आंकना संभव न हो। उपलब्ध पूंजी का पर्याप्त भाग स्वास्थ्य और ि ाक्षा सेवाओं,

अच्छी संचार सुविधाओं, पीने के पानी और सामाजिक कल्याण के लिये अनिवार्य रूप से खर्च करना होगा। समाज के वंचित वर्ग यथा हरिजनों, तपरीवास और विमुक्त जातियों सहित पिछडे वर्गों, अपाहिजों, बूढों तथा निर्बलों की भलाई के कार्यक्रमों की ओर भी वि ोश ध्यान देने की जरूरत है। इन सब लक्ष्यों की प्राप्ति उपलब्ध वित्तीय साधनों के अंदर ही करनी होगी अन्यथा ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि इसके कारण पैदा होने वाली मुद्रास्फीति से विकास का मूल उद्दे य ही नश्ट हो जाये। अन्तिम बात यह है कि हम चाहें जो भी रास्ता अपनाएं और हमारे उद्दे य चाहे जो भी हों तथा हमारे वित्तीय एवं अन्य प्रतिबंध कुछ भी हों, प्रगति के कार्यक्रमों का, राज्य के लोगों की फौरी इच्छाओं और आकांक्षाओं का द र्शना आव यक है। राश्ट्रीय विकास परिशद ने पिछले मास की 13 व 14 तारीखों को अपनी बैठकों में इन सब बातों पर विस्तार से विचार विम र्श किया और एक मत होकर यह फैसला किया कि नई योजना को क्या दि ाा दी जाये। सामान्य जनहित के उद्दे य की पूत्रि के लिये तथा राश्ट्र एवं अपने नागरिकों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए यह आव यक हो जाता है कि हम इन कार्यक्रमों को अधिक से अधिक तीव्रता एवं योग्यता के साथ कार्यान्वित करें। इस संबंध में दो मत हो सकते हैं कि इतना कुछ काफी है या नहीं, फिर भी यह कोई नहीं कह सकता कि हमने जो कदम उठायें हैं अथवा जो कदम उठाने वाले हैं, वे अत्याधिक हैं। राश्ट्रीय योजना के संबंध में हमारी प्रधानमंत्री जी ने राश्ट्रीय विकास परिशद में कहा था कि

"यह योजना अभिवांछनीय एवं संभावना की सीमा के मध्य का श्रेश्ठतम प्रयास है जो संभव है उससे अधिक पाने की चेश्टा से ही हम अपने में निहित सामर्थ्य को चरमसीमा तक पहुंचा सकेंगे।" हमारा वि वास है कि हमारी राज्य योजना और कार्यक्रमों के संबंध में भी यही बात ठीक तरह से लागू होती है।

वार्शिक योजना 1980–81

योजना संबंधीयस गतिविधियों के बारे में, वर्श 1980–81 का आरम्भ 240.50 करोड रूपये के अनुमोदित योजनागत परिव्यय से हुआ। माननीय सदस्यों को यह जान कर हर्श होगा कि हमने इस परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि की है और सं ाोधित अनुमानों में राज्य योजना का 253.78 करोड रुपये का परिव्यय भाामिल हैं स्पश्ट है कि हरियाणा के कार्यकु ाल प्र ाासन ने विकास गतिविधियों को कार्यान्वित करने में भात प्रति ात सफलता प्राप्त की। राज्य का यौजना परिव्यय और भी अधिक होता। परन्तु खेद है कि हमारे अधिक से अधिक प्रयत्नों के बावजूद और बावजूद इस बात के इस मसले को ऊंचे से ऊंचे स्तरों पर उठाया जाता रहा, फिर भी पंजाब सरकार ने सतलुज यमुना योजक नहर परियोजना पर कार्य आरम्भ नहीं किया। राज्य बजट दस्तावेज के सं ाोधित अनुमानों में, जिसमें केन्द्रीय सैक्टर और केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना स्कीमैं भी भाामिल हैं, परन्तु जिसमें बिजली बोर्ड की योजना का भाग और कुछ अन्य स्कीमें भाामिल नहीं हैं, 250.72 करोड रुपये का योजनागत व्यय द ार्या

गया है जबकि 1980–81 के बजट अनुमानों में इस हेतु 230.69 करोड रुपये की व्यवस्था की गई थी। इन आंकड़ों पर नजर डालते ही पता चल जाता है कि वर्श के दौरान योजनागत व्यय की रफ्तार में काफी वृद्धि हुई है। कुछ एक महत्वपूर्ण वृद्धियां उल्लेखनीय हैं।

इस बात को सभी जानते हैं कि हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम अन्य कार्यों के साथ साथ, जल मार्गों को पक्का करने के काम में लगी हुई हैं। इन कार्यों पर खर्च होने वाले पूंजी निवे ा और उसके ब्याज को पुनः अदायगी के भाग से लाभानुभोगियों को आं ाक राहत पहुंचाने के उद्दे य से यह निर्णय किया गया था कि 2.50 एकड तक की जोत वाले किसानों को इस देनदारी से छूट दे दी जाये और 2.50 एकड से अधिक जोत वाले किसानों की देनदारी में 50% की छूट दे दी जाए। (थम्पिंग) तथापि यह सुनि ाचत करने के लिये कि निधि की कमी हो जाने से निगम की गतिविधियों को धक्का न पहुंचे, 7.30 करोड रुपये के मूल उपबन्ध के अतिरिक्त निगम को 5.50 करोड रुपये की रा ा मुहैया कर दी गई है। राज्य सरकार ने यह बात सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली है कि वह इस खाते में वसूली कीइ कमी को भविश्य में भी पूरा करेगी। यह कदम उठाकर यह सुनि ाचत कर लिया गया है कि लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम अपनी स्कीमों के निश्पादन की रफ्तार न केवल बरकरार रखेगी बल्कि इसमें तीव्रता लायेगी। राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों के लिए

अनिवार्य रूप से रोजगार जुटाने के लिये, भारत सरकार की सहायत से चालू वर्श के दौरान, राश्ट्रीय देहती रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत एक करोड रुपये का प्रवधान किया गया है। कई वर्शों से चालू ग्रामीण सडक निर्माण कार्यक्रम में, इस अवधि के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हुई हैं संचार व्यवस्था को और सुदृढ बनाने के लिए सरकार ने एक क्रै ा कार्यक्रम के माध्यम से, प्रत्येक गांव में पक्की सडक पहुंचाने का निर्णय लिया है। (थम्पिंग) यह राज्य की एक महान उपलब्धि होगी। इसी प्रकार राज्य का सडक परिवहन उपक्रम, जिसे दे ा के ऐसे उपक्रमों में वि ोश ख्याति प्राप्त है, में अतिरिक्त सुधार लाने के उद्दे य से हरियाणा राज्य परिवहन का योजनागत परिव्यय 7.30 करोड रुपये से बढा कर 9.70 करोड रुपये कर दिया गया था। (थम्पिंग) ताकि विभाग बसों की तादाद बढा सके और विभिन्न स्थानों पर यात्रियों को ज्यादा सुविधायें प्रदान कर सके। इसके अनुसार देहाती जल सप्लाई स्कीम के लिये, राज्य योजना में जहां पहले 7 करोड रुपये का उपबंध था, वहां अब इस उपबंध को बढा कर 8.65 करोड रुपये कर दिया गया है। (थम्पिंग) यह उपबंध त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (Accelerated Rural Water Supply Programme) के अन्तर्गत खर्च किये जाने वाले 3.20 करोड रुपये के अतिरिक्त होगा। वे लोग जो मेवात क्षेत्र की समस्याओं की वि ोश जानकारी रखते हैं और इनके संबंध में सहानुभूति पूर्ण नजरिया रखते हैं, यह जान कर प्रसन्न होंगे कि इस क्षेत्र के सर्वतोमुखी और तीव्र विकास संबंधी सरकार के वायदे के दृश्टिगत, मेवात विकास बोर्ड के लिये 1.25

करोड रुपये की रा ि ा स्वीकृत की गई हैं (थम्पिंग) जरूरतमंदों को उचित दामोयसं पर अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई को सुनि ि चत करने की समस्या का जिक्र मैंने पहले भी किया है। इसे हल करने के विचार से सरकार ने सहकारी खपतकार संघ को वर्श के दौरान एक करोड रुपये की रकम स्वीकृत की है, ताकि यह सरकार क्षेत्र में खपतकार भण्डारों के जाल को फैला सके। पिछले दिसम्बर के अंत तक 2000 से अधिक आबादी वाले 1355 देहातों में उचित दामों की दुकानें खोली जा चुकी हैं। (थम्पिंग) हमारा आरम्भिक नि ाना यह है कि प्रत्येक ऐसे गांव में एक दुकान अव य खोल दी जाये। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य में जमीन पर आबादी के दबाव के कारण अर्थव्यस्था में उत्पन्न होने वाली कठिनाई को प्रभाव ाली ढंग से रोकने के लिये उद्योगौं को आधार बनाना जरूरी है, सरकार ने इस क्षेत्र के मूल परिव्यय में 2.72 करोड रुपये की वृद्धि की है। मुझे वि वास है कि विरोधी मंचों पर बैठे हुये, माननीय सदस्य, यह जानकर प्रसन्न होंगे, कि बिजली दर और उद्योगों के भाुल्क के समस्त भार को तर्कसंगत बनाने से संबंधित कार्यवाही वर्श के दौरान मुकम्मिल हो चुकी है और सरकार ने औद्योगिक इकाइायों को वर्गीकृत आधार पर बिजली भाुल्क से आं ि ाक राहत स्वीकार करने की स्कीम चालू की है जिसके कारण उद्योग क्षेत्र के परिव्यय में काफी इजाफा हुआ है। सरकार को वि वास है कि इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन के स्तर में वृद्धि होगी। और राज्य में ज्यादा खु ाहाली आयेगी। साल के मध्य में की जाने वाली प्रमुख

तबदीलियों में से एक महत्वपूर्ण तबदीली यह है कि 'हरियाणा पिछडे वर्ग और आथ्रिक रूप से कमजोर वर्ग' निगम (ीघ्र ही जिस का नाम बदल कर 'हरियाणा पिछडे वर्ग निगम कर दिया जायेगा) की स्थापना की गई है। यह निगम पिछडे वर्ग के सदस्यों को वित्तीय सहायता तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करेगी। इस निगम के लिये एक करोड रुपये का उपबंध किया गया है और उन्होंने कई एक लाभदायक स्कीमें तैयार कर ली हैं। राज्य के योजनागत कुल सं ाोधित परिव्यय में हरिजनों के कल्याण के लिये वि ोश संघटक योजना (Special Component Plan) की 26 करोड रुपये से अधिक की रकम भाामिल है। हरिजनों को आवास बोर्ड की एजेंसी द्वारा सस्ते दामों के मकान मुहैया करने की नई योजना इस वर्ग के लाभ के लिये उपलब्ध स्कीमों के इलावा भाुरू की गई है। (थम्पिंग) इसके अतिरिक्त बहुत सी अन्य गतिविधियों का योजनागत परिव्यय बढाया गया है, चाहे वह अपेक्षाकृत थोडा ही क्यों न हो।

आज जनता अथवा गरीब और पद दलित लोगों के स्तर को ऊपर उठाने से संबंधित सरकार की नीति की प्रमुख दि ाा के साथ पूरा न्याय करने के लिये चालू वर्श के प्रमुख कार्यक्रमों के वित्तीय आबंटनों के परिवर्तनों का उल्लेख कर देना मात्र काफी नहीं होगा। यद्यपि इन आबंटन का विस्तृत ब्यौरा अन्य स्थानों पर दिया गया है और मैं वि ाश्अ मदों के संबंध में बाद में उल्लेख करूंगा। यहां इस बात का जिक्र कर देना अनिवार्य होगा कि

हमारी सरकार ने हमारी पार्टी के आर्थिक कार्यक्रमों को जिसे सामान्यतः 20 सूत्रीय कार्यक्रम के नाम से पुकारा जाता है, कार्यान्वित करने की दि ाा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और वह आगे भी ऐसा ही करती रहेगी। उदाहरण के तौर पर उचित दामों की बहुत सी दुकानें खोली गई हैं। राश्ट्रीय परमिट स्कीम के अन्तर्गत ट्रक चालकों को परमिट जारी किए गये हैं और परमिट भीघ्र ही जारी किए जायेंगे। वित्त वर्श के अंत तक पात्र व्यक्तियों को फालतू भूमि आबंटित करने के लिये हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए पाठयपुस्तकों की व्यवस्था की जा रही है और जहां कहीं भी संभव है वहां अनुत्पादक व्ययों में बचत की जा रही है।

योजनेतर व्यय 1980–81

वर्श 1980–81 के दौरान योजना व्यय के रूप में वर्गीकृत खर्चे की मदें ही केवल ऐसी मदें नहीं हैं कि जहां काफी इजाफा किया गया है। योजनेतर वर्गीकरण के अन्तर्गत भी लेखों के लगभग सभी भीशार्ों के अन्तर्गत अतिरिक्त निधियों का उपबंध किया गया है। कुछ वृद्धियां सरकार के वेतन सं ाोधन के निर्णय के फलस्वरूप वेतन और भत्तों की वृद्धि प्रकट करती हैं और कुछ महंगाई के कारण प्र ाासकीय खच्र को पूरा करने के लिये हुई हैं। ऋण अदायगी के प्रावधानों में भी वृद्धि की गई है जो कि

अधिकां ा रूप में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त होने वाले अधिक कर्जों द्वारा बराबर हो जाती है। योजनेतर विकास सम्बंधी बहुत सी गतिविधियों के लिये उपबंधों में पर्याप्त वृद्धि की गई है। ि ाक्षा पर योजनेतर खर्च 11.48 करोड रुपए बढ गया हे जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कुरुक्षेत्र वि वविद्यालय को अधिक ग्रांट, प्राइवेट कालेजों के संधारण अनुदान के फार्मूले में सुधार, प्रान्तीयकृत स्कूलों के अध्यापकों के वेतनों में सुधार और ि ाक्षा संस्थाओं का दर्जा बढाने तथा गैर सरकार ि ाक्षा संस्थाओं में ि ाक्षा का स्तर ऊंचा होगा। सहकारिता के क्षेत्र में सरकार से सहकारी समितियों को कर्जों का अन्तकरण 6.12 करोड रुपये बढा दिया गया हे जिसमें से 4.03 करोड रुपया हरियाणा सहकारी सप्लाई और विपणन संघ को दिया गया है ताकि वह किसानों के लाभ के लिए कृशि सम्बंधी अनिवार्य निवे ा खरीद सके और उसका भण्डार कर सके। गन्ना उत्पादकों के हित में राज्य सरकार द्वारा गन्ने का अपेक्षाकृत ऊंचा मूल्य निर्धारित किया जाने के कारण सहकारी चीनी मिलों को कार्य चालन पूंजी का आधार मजबूत बनाने के लिये कर्ज के रूप में 1.59 करोड रुपये की रकम दी गई थी। स्मरण रहे कि गन्ने की चालू फसल के लिये भारत सरकार द्वारा घोशित गन्ने के 13 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतक मूल्य के मुकाबले में राज्य सरकार ने 23 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य की घोशणा पहली ही कर दी थी (थम्पिंग) जिसे हाल ही में बढाकर 26 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया हैं (थम्पिंग) इसी प्रकार हरियाणा डेरी विकास निगम को 50 लाख

रुपए की रा ि ा दी गई थी ताकि वह दुग्ध उत्पादनकर्त्ताओं को दूध की खरीद का मूल्य समय पर चुकता कर सके। हरियाणा कृशि उद्योग निगम को भी कार्य चालन पूंजी के लिये कर्ज के रूप में 2.16 करोड रुपए की रकम दी गई थी ताकि वह अपनी गतिविधियों का क्षेत्र फैला सके। इसी प्रकार हरियाणा राज्य उद्योग विकास निगम कोग कार्य चालन पूंजी के रूप में प्रयोग करने के लिए 77 लाख रुपए की रकम पे ागी दी गई थी ताकि वह अपनी सहायक यूनिटों की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सके। हमारे किसानों की मुसीबतें पिछले वर्श अप्रैल से ही प्राकृतिक आपदाओं के कारण भुरू हो गई थीं। अप्रैल 1980 में ओलावृश्टि के बाद राज्य के एक भाग में बाढ और दूसरे भाग में विकट सूखे के दोहरे संकट ने उन्हें लगातार यातनाएं दी हैं तथा इसके बाद अक्तूबर 1980 में और दोबारा हाल ही में ओलावृश्टि से उनकी हालत और भी दयनीय हो गई है। इसके दृश्टिगत इन्हें राहत देने के लिए तकाबी कर्जों की रकम 1.84 करोड रुपये से बढाकर 2.34 करोड रुपये कर देनी पडी है तथा इसके अतिरिक्त 10.61 करोड रुनए से कई अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की गई है, जिसमें पानी निकालने के लिए 2 करोड रुपये निः ाुल्क राहत के लिये 4.86 करोड रुपये राहत के लिए आरम्भ किए गए निर्माण कार्यों के लिए 2.50करोड रुपये तथा अन्य मदें यथा चारा और कृशि निवे ाों के लिए सहायतानुदान, मनुश्यों और प ाुओं के लिए दवाइयों की सप्लाई भाामिल हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य कोश पर 12.45 करोड रुपए के खर्च का भार पडा है तथा

इसके अतिरिक्त भूराजस्व, आबियाना तथा तकावी की वसूलियों की मुलतवी और मुआफी के कारण 4.24 करोड रुपए तक के राजस्व की हानि हुई है। फसलों प ाुधन और गैर सरकारी सम्पत्ति को होने वाली क्षति के मुकाबले तथा लोगों द्वारा सहन किए गए कश्अ को देखते हुए राज्य व्यवस्था पर पडने वाला भार महत्त्वहीन हो जाता है। इस विपति के सम्मुख उनका धैर्य और संकल्प सराहनीय है। पुलिए विभाग के खर्च में भी 4.08 करोड रुपये की वृद्धि हाने पर उसका खर्च 19.20 करोड रुपए हो गया है। इसमें वेतन आयोग की सिफारि ाों के कारण वेतन और भत्तों की वृद्धि का पर्याप्त भाग भाामिल है तथा कुछ सीमा तक महंगाई भी इसके लिए जिम्मेवार है। इसमें पुलिस चौकियों का दर्जा बढाकर थाना बनाने का खर्च, पुलिस नफरी में वृद्धि और आज के अ ाांत काल में प्र ाासन के इस महत्वपूर्ण अंक को आधुनिक रूप देने पर किया खर्च भाामिल है। कर्ज भार के भुगतान के लिए जो कि मूल रूप से भरतीय रिजर्व बैंक के अर्थोपाय पे ागियों के लिए प्राप्त किया गया था, 63.34 करोड रुपए अधिक खर्च करना पडा (यद्यपि यह रा ि ा केन्द्रीय सरकार तथा अन्य साधनों से प्राप्त कर्जों और पे ागियों के रूप में प्राप्त हुई अधिक रा ि ा से पूरी हो जाती है।) इसके फलस्वरूप सामेकित निधियों से योजनेतर कुल खर्च 488.80 करोड रुपए से बढकर 601.78 करोड रुपए हो गया है अर्थात इसमें 112.98 करोड रुपए की वृद्धि हुई है। योजना व्यय जो कि राज्य के 1980–81 के बजट अनुमानों में 1060.33 करोड

रुपये प्रत्याि ात था अब 233.17 करोड रुपए की वृद्धि के बाद सं ाोधित अनुमानों में 1293.50 करोड रुपए हो गया है।

प्राप्तियां 1980–81 व लेखे 1979–80

वर्श 1980–81 के बजट अनुमानों के अनुसार प्राप्तियां 1046.70 करोड रुपये होने का अनुमान था जिसमें 220.98 करोड रुपए की वृद्धि के बाद यह 1267.68 करोड रुपये तक पहुंच गई। प्राप्तियों में इस सुधार के अतिरिक्त अथ ोश के आंकडों में भी सुधार हुआ जो चालू वर्श का बजट प्रस्तुत करते समय 19.32 करोड (नफी) अनुमानित था जबकि बाद में सुधार के बाद 12.02 करोड रुपए (नफी) रह गया था। इस अतिरिक्त राि ा के उपलबध होने के कारण योजना एवं योजनेतर दोनों पक्षों में अधिक खर्च संभव हो सका हैं चालू वर्श के लेखे में मुख्य सुधार का जिक्र करने से पहले वश्र 1979–80 के लेनदेन से उभरने वाली स्थिति पर दुश्टिपात करना उचित होगा। इस तुलनात्मक अध्ययन से इस बात का पता चलेगा कि वर्श 1979–80 के सं ाोधित अनुमानों के अनुसार समेकित निधि में कुल 604.41 करोड रुपए की प्राप्ति का अनुमान था जबकि वास्तविक आंकडों के अनुसार वसूलियां 622.01 करोड रुपए हुई जिससे 17.60 करोड रुपए के सुधार का पता चलता है। दूसरी ओर समेकित निधि से कुल खर्च 654.46 करोड रुपए होने का अनुमान था जो कम होकर 645.43 करोड रुपए रह गया अर्थात यह 9.03 करोड रुपए कम हुआ। लोक लेखा अनुभाग में वश्र 1979–80 के सं ाोधित अनुमानों के अनुसार निबल उपचय

26.70 करोड रुपए होने का अनुमान था जो घटकर 8.44 करोड रुपये रह गयां समेकित निधि की प्राप्तियों में निम्नलिखित कारणों से सुधार हुआ। आयकर में राज्य का हिस्सा 0.78 करोड रुपए, आबकारी भाुल्क की वसूली 2.02 करोड रुपए, बिक्री कर की वसूली 0.62 करोड रुपए, माल और यात्रियों के परिवहन के उदग्रहण से कर की वसूली 0.83 करोड रुपए गन्ने पर खरीद कर 0.96 करोड रुपए बयाज प्राप्तियां 3.34 करोड रुपए और अनेक प्रकार की घटा बढी जिनमें प्रमुख हैं: सहायतानुदान 1.67 करोड रुपए तथा खाद्यान्न की खरीद के लिये भारतीय स्टेट बैंक से लिया गया ऋण 9.50 करोड रुपए। इस घटा बढी की विस्तृत व्याख्या बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दी गई है।

जहां तक वर्श 1980–81 का संबंध है अधिक प्राप्तियां जिनका मैंने पहले जिक्र किया है, अन्य स्त्रोतों के साथ साथ निम्नलिखित से हुई हैं। केन्द्रीय करों से अधिक अन्तरण 3.91 करोड रुपए, अधिक सहायतानुदान 1.32 करोड रुपये, भारत सरकार से अधिक ऋण 20.95 करोड रुपए और वित्तीय संस्थाओं से अधिक ऋण 2.10 करोड रुपये। इसके विपरीत भारतीय स्टैट बैंक से लिया गया ऋण 30 करोड रुपए घट गया है क्योंकि खद्यान्न की खरीद राज्य सरकार के खाद्य विभाग के इलावा दूसरी एजेंसियों द्वारा ज्यादा की गई है। चूंकि इन ऋणों की पुनः अदायगी वर्श के अंदर ही कर दी जानी है। अतः इसका बजट पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। राज्य करों में भी आ ाा के मुताबिक

वृद्धि आई है तथा जलवायु एंव आर्थिक परिस्थितियों के प्रतिकुल होने और राजस्व वसूली के बडे पैमाने पर मुआफ और मुलतवी कर दिए जाने के बावजूद इनकी वसूली में कुल मिलाकर 20.37 करोड रुपए की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का एक अं ा यात्रियों और माल के कर की अधिक वसूली का परिणाम है (3.21 करोड रुपए) जो कि यात्रि किरायों में 25% वृद्धि कर देने के कारण हुई हैं करों की अधिक वसूलियां, कर संबंधी कानूनों को सुचारू रूप से तथा दृढता से लागू करने का परिणाम हैं कर भिन्न राजस्व के अत्यंत महत्त्वपूर्ण वृद्धि, हरियाणा राज्य परिवहन के राजस्व में हुई है। (5.35 करोड रुपए) जो मुख्यत यात्रि किराए में वृद्धि तथा बेहतर प्र ाासन के कानण है लेकिन परिचालन की अधिक लागत और महंगाई के कारण यह वृद्धि लगभग समाप्त हो गई है क्योंकि हरियाणा राज्य परिवहन का खर्च भी 5.18 करोड रुपये बढ गया है। हमारे वर्श 1980–81 के वित्त संबंधी लेनदेनों के संबंध में महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन सं ाोधन और बजट प्रस्तुत करने के बाद दी गई महंगाई भत्ते की चार किस्तों के प्रभाव के इलावा योजना व्यय में अत्यधिक वृद्धि और वर्श के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्यकोश को होने वाली 16.69 करोड रुपए की गिरावट के बावजूद भी वर्श के अंत तक का घाटा उस घाटे से कम रहेगा जो बजट अनुमानों में प्रत्याि ात था।

छठी योजना 1980–85

मैंने छठी पंचवर्शीय योजना (1980–85) का पहले भी जिक्र किया है। इसे हाल ही में अंतिम रूप दिया गया है। कुल राश्ट्रीय योजना 172210 करोड रुपये की नि ि चत हुई है। इसमें राज्यों और संघीय क्षेत्रों की कुल योजना 50250 करोड रुपए की है। इस रकम में हरियाणा की पंचवर्शीय योजना 1800 करोड रुपए है जो कि राज्यों और संघीय क्षेत्रों की योजना का लगभग 3.5% है। जब इस बात की ओर ध्यान दिया जाए कि हमारा राजय भारतीय संघ की कुल आबादी का केवल 2% से कुछ कम है तो यह बात बिल्कुल स्पश्ट हो जाती है कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति परिव्यय दे ा के प्रति व्यक्ति परिव्यय से अधिक है और कुल रा ि ा के दृश्टिकोण से हरियाणा की छठी पंचवर्शीय योजना पांचवी पंचवर्शीय योजना के परिव्यय से तिगुनी है। परन्तु इस उपलब्धि का वास्तविक महत्व न तो प्रति व्यक्ति परिव्यय के आंकडों में निहित है और न ही पिछली योजना की अपेक्षा इसके बडा होने पर निभ्रर करता है। वस्तुतः असली महत्व का इस बात से पता चलता है कि योजना आयोग और भारत सरकार ने इस बात को माना है कि हमारे राज्य के लोग तीव्र विकास के योग्य हैं और इसके पात्र भी हैं और योजना आयोग ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि राज्य सरकार भीघ्र विकास को सुनि ि चत करने के लिये कटिबद्ध है। यहां कुछ परिव्ययों और कार्यक्रमों का संक्षिप्त देना संगत रहेगा।

अर्थ व्यवस्था को निर्दिश्ट करने वाले क्षेत्रों को वि ोश महत्व दिया जा रहा है। यह बात वि ोश उल्लेखनीय है कि कृशि एवं सहकारिता के संबंधित क्षेत्रों के लिए 284.57 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है जो कि कुल योजना का 15.8 प्रति ात है जबकि इसके मुकाबले में पांचवीं योजना में यह 9.6% था। इसी प्रकार छठी योजना में जल एवं बिजली विकास के लिए 1021.25 करोड रुपए का उपबंध किया गया है। जबकि पांचवी योजना में इसके मुकाबले में 369.70 करोड रुपए की व्यवस्था की गई थी। छठी योजना में सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिए 277.47 करोड रुपए का प्रावधान है जबकि पांचवी योजना में इसके लिए 76.88 करोड रुपया रखा गया था। इससे चार गुना वृद्धि का पता चलता है। छठी योजना में परिवहन और संचार के लिए 169.50 करोड रुपए का उपबंध किया गया है जबकि इसके मुकाबले में पांचवीं योजना में 49.61 करोड रुपए का उपबंध था तथा उद्योग एवं खनिज के लिये पांचवी योजना तें 12.71 करोड रुपये से बढाकर छठी योजना में 30.86 करोड रुपये की व्यवस्था कर दी गई हैं इस तरह हरियाणा में छठी योजना का प्रति व्यक्ति निवे ा 1343.28 रुपए है जबकि इसके मुकाबले में पांचवीं योजना का प्रति व्यक्ति निवे ा 509.62 रुपए था।

छठी योजना के परिव्ययों से पता चलता है कि इसका उद्दे य ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में अधिक से अधिक वृद्धि लाना हैं। अतः जल एवं बिजली साधनों के विकास कृशि एवं संबंधित क्षेत्रो,

परिवहन एवं संचार तथा सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिए अधिक से अधिक उपबंध किया गया है। इसके साथ साथ पिछडे वर्गों, पिछडे क्षेत्रों और हरिजनों के उत्थान के लिए वि ाश्ट स्कीमें तेयार की गई हैं। (ाोर)

इस योजना के कुछ एक प्रमुख नि ाानें इस प्रकार होंगे : 1984–85 तक अनाजों का उत्पादन 50.32 लाख टन से 80 लाख टन बढाना, गन्ने का (गुड़ के रूप में) 3.95 लाख टन से 9 लाख टन बढाना, तिलहन 0.72 लाख टन से 1.80 लाख टन और कपास 5.28 लाख गांठों से 7.70 लाख गांठें। (थम्पिंग) बिजली पैदा करने की क्षमता 1077 मैगावाट से बढाकर 1648 मैगावाट और सिंचाई क्षमता 17.69 लाख हैक्टेयर से बढाकर 19.20 लाख हैक्टेयर करना तथा प्रयोग 16.30 लाख हैक्टेयर से बढाकर 17.96 लाख हैक्टेयर करने का हमारा इरादा हैं छठी योजनाम ं 1.27 लाख लोगों के लिए सीधे और निरन्तर रोजगार के साधन जुटाए जाएंगे तथा निर्माण कार्यों पर 6.71 लाख व्यक्ति वर्श का रोजगार उपलब्ध होगा।

वर्तमान बजट अनुमान छठी पंचवर्शीय योजना तैयार होने के बाद राज्य सरकार का पहली बजट है यद्यपि वर्श 1981–82 इस योजना का दूसरा साल है। वह योजना जिन सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में तैयार हुई है, उन पर प्रका ा डाल लेने के बाद तथा साधनों एवं अन्य कठिनाइयों के दृश्टिगत जिन उद्दे यों की पूर्ति के लिये इसे कार्यान्वित किया जाना है यह

उचित होगा कि हम अगले वर्श के सारे कार्यक्रमों को प्रत्येक मद पर अलग अलग से दृश्टिपात करें।

वर्श 1981–82 के कार्यक्रम

बजट अनुमानों से कुल 1408.19 करोड रुपये के व्यय का पता चलता है जिसमें योजना व्यय के 285.04 करोड रुपये तथा समेकित निधि में से योजनेतर व्यय के 636.05 करोड रुपये और लोक लेखा अनुभाग से 487.10 करोड रुपये का खर्च भाामिल है। योजना व्यय के निर्दिश्ट आंकडों में राज्य योजना स्कीमों और केन्द्रीय क्षेत्र के स्कीमों का खर्च भाामिल है। फिर भी इन आंकडों से राज्य का कुल योजना व्यय लक्षित नहीं होता क्योंकि इसमें बिजली बोर्ड का योजना व्यय भाामिल नहीं है जो कि वह अपने साधनों से खर्च करेगा। इसी प्रकार इस योजना व्यय में स्वायत्त निकायों के उन अनेक कार्यक्रमों का खर्च भी भाामिल नहीं है, जो वे पूरी तरह से सीधे बाह्य साधनोसं से करेंगे। राज्य का अनुमोदित योजना परिव्यय 290 करोड रुपये है। केन्द्रीय क्षेत्र योजना 30.10 करोड रुपये हैं।

वर्श 1981–82 के कुल 290 करोड रुपये के योजनागत परिव्यय में से कृशि तथा इससे संबंधित सेवाओं के लिये 53.82 करोड रुपये, पानी और बिजली विकास के लिये 157.46 करोड रुपये, उद्योग और खनिजों के लिये 5.79 करोड रुपये परिवहन और संचार के लिये 26.57 करोड रुपये और सामाजिक एवं

सामुदायिक सेवाओं के लिये 42.96 करोड रुपये का उपबंध किया गया हैं इन परिव्ययों से पता चलता है कि इनमें वर्श 1980–81 की वार्शिक योजना की अपेक्षा महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है और इनसे इस बात का भी पता चलता है कि सरकार बहुत ऊंचा वृद्धि दर प्राप्त करने के लिये कटिबद्ध है। इस अवसर पर मैं माननीय सदस्यों को 1981–82 की वार्शिक योजना की मोटी मोटी महत्त्वपूर्ण वि ोशतायें ही बताना चाहूंगा।

वर्श 1981–82 के दौरान सिंचाई की बडी और माध्यमिक स्कीमों को चलाने के लिये 59.50 करोड रुपये का उपबंध किया गया है। इसमें 6 करोड रुपये का वह खर्च भी भाामिल है जो पंजाब क्षेत्र में सतलुज यमुना योजक नहर पर खर्च किया जाना प्रस्तावित है और सरकार इस बात के लिये निरन्तर प्रयत्न ाील है कि यह कार्य पंजाब के क्षेत्र में आरम्भ हो जाये। सिंचाई के लिये जल का अधिक से अधिक लाभ उठाने क लिये वर्तमान जलमार्गों को पक्का करने का काम जारी रहेगा और इस कार्य के लिये वि व बैंक की सहायता से चलने वाले प्रोजैक्ट के पहले चरण के भीघ्र ही मुकम्मिल हो जाने की सम्भावना है। इसके मुकम्मिल होने पर लगभग 25 करोड वर्ग फुट जलमार्ग पक्का हो जायेगा जिसके फलस्वरूप 1500 क्यूसिक जल व्यर्थ होने से बच जायेगा। जलमार्गों को पक्का करने एवं अन्य विकास कार्यों के लिए लगभग 400 करोड रुपये की एक द्वितीय परियोजना

वि व बैंक की सहायता से आरमी की जानी विचाराधीन है। (Thumping)

कृशि क्षेत्र के अत्यंत महत्त्वपूर्ण निवे ा अर्थात जल की सप्लाई को सुनि ित करने के साथ साथ हम कृशि एवं उद्योग दोनों के लिए दूसरे अनिवार्य निवे ा अर्थात बिजली की पर्याप्त सप्लाई के लिये भी प्रयत्न ील हैं। बिजली की वर्तमान उपलभ्यता को बढाने के लिये छोटी और लम्बी अवधि वाली दोनों प्रकार की कार्यवाहियां की जा रही हैं। इस उद्दे य के लिये 1981–82 की वार्शिक योजना में 80.46 करोड रुपये के योजनागत परिव्यय का उपबंध किया गया है। छोटी अवधि में बिजली की उपलभ्यता को बढाने के लिये अन्य साधनों के साथ साथ कुछ साधन हैं। फरीदाबाद थर्मल विस्तार इकाई-III, पानीपत थर्मल परियोजना चरण-II और चरण-III तथा पि चमी यमुना नहर पन बिजली परियोजना चरण–1। राज्य सरकार इस बात के लिये प्रयत्न ील है कि उसे यमुनागर थर्मल बिजली परियोजना के लिये भीघ्र ही अनुमति मिल जाये, जिससे कि 800 मैगावाट बिजली का उत्पादन होगा। (Thumping) इसी प्रकार नाथपा झाकरी पन बिजली परियोजना को जिस पर 534 करोड रुपये की अनुमानित लागत आयेयगी और जिससे लगभग 1020 मैगावाट बिजली पैदा होगी। हाल ही में हुये समझौते के अनुसार केन्द्रीय सरकार की सहायता से त्रिपक्षीय आधार पर भुरू करने के प्रयास किये जा रहे हैं चालू वर्श में राज्य की सभी हरिजन बस्तियों में बिजली लगाने का काम तत्परता के साथ किया जा रहा है और सरकार को आ ाा है कि

जून 1981 के अंत तक ऐसी सभी बस्तियों की गालियों में बिजली मुहैया कर दी जायेगी। मार्च 1985 के अंत तक सभी देहातों की गलियों में बिजली मुहैया करने का एक अन्य कार्यक्रम चालू किया गया है। (Thumping)

15.00 बजे।

पिछले कुछ वर्शों में खाद्यान्न में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है क्योंकि क्षेत्र की प्रत्येक इकाई के उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है। इससे पता चलता है कि सिंचाई विस्तार, बढिया बीजों, उर्वरकों, ऋण तथा अन्य निवे ाों की सुनि चित सप्लाई संबंधी हमारी मूल नीति पूरी तरह सफल रही हैं वर्श 1981–82 के दौरान भी इसी नीति का अनुसरण किया जायेगा और इस उद्दे य के लिये बिजली और सिंचाई संबंधी मुख्य एवं माध्यमिकि स्कीमों के प्रावधान के अतिरिक्त 47.54 करोड रुपये की व्यवस्था केवल कृशि क्षेत्र के लिए कर दी गई है। कृशि अनुसंधान और विस्तार सेवा की ओर भी उचित ध्यान दिया जा रहा है। कृशि क्षेत्र में की गई प्रगति का इस बात से पता चलता है कि पिछले कई वर्शों के दौरान लगातार मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद उत्पादन के स्तर को किसी प्रकार का गहरा धक्का नहीं लगा है। हमें आ ाा है कि हम वर्श 1981–82 के दोरान अपने पैदावार के नि ााने को पूरा कर लेंगे जो इस प्रकार हैः खाद्यान्न 68.20 लाखटन, कपास 6.80 लाख गांठें, गन्ना (गुड़ के रूप में) 7 लाख टन और तिलहन 1.55 लाख टन। यह नि ाना गहन और विस्तृत का त के द्वारा और

क्षेत्र की प्रत्येक इकाई की उपज बढा कर पूरा किया जायेगा। समय पर इनपुट सप्लाई करने की ओर ध्यान दिया जायेगा तथा पौधों की रक्षा करने के काम पर बल दिया जायेगा जैसे कि इस वर्श किया गया जबकि धान और गेहूं में हानिकारण खरपतवार की रोकथाम के लिए 1.30 करोड रुपये की अतिरिक्त रा ि ा की व्यवस्था की गई थी। मंडी में आने वाले अधिक बिक्री के माल का ठीक प्रकार से प्रयोग करने के विचार से 1981–82 के अंत तक व्यवस्थित मंडियों की संख्या 88 से बढाकर 92 कर दी जायेगी। फसलों के बीमे की स्कीम चालू करने का सरकार का विचार है जिसका उद्दे य यह होगा कि वह असहाय किसानों की प्रकृति के प्रकोप से बचा सके। देहातों के समेकित विकास का कार्यक्रम जो कि हमारे गरीबी हटाने के कार्यक्रम का प्रमुख साधन है। राज्य के सभी ब्लाकों में चालू कर दिया गया है और ऐसा प्रस्ताव है कि वर्श 1981–82 के दौरान 6 लाख रुपये प्रति ब्लाक खर्च करके प्रत्येक ब्लाक के कम से कम 600 परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सकेगा। (थम्पिंग) इसके लिए प्रत्येक ब्लाक में चालू वर्श के प्रावधान की अपेक्षा एक लाख रुपये प्रति ब्लाक अधिक प्रावधान किया गया है। इनमें से दो तिहाई लाभानुभोगी हरिजन होंगे।

मिश्रित खेती को बडे पैमान पर बढावा देने के विचार से प ाुपालन, मछली पाल और डेयरी विकास के निमित 3.05 करोड रुपये के परिव्यय का उपबंध किया गया है। प ा चिकित्सा

सहायता में सुधार करने के विचार से वश्र 1981–82 में 50 प ा डिस्पैंसरियां खोली जायेंगी तथा 25 डिस्पैंसरियों एवं स्टाकभैन केंद्रों का दर्जा बढाकर उन्हें प ा हस्पताल एवं प्रजनन केंद्र बनाया जायेगा। यह कार्य इस साल खोली जानी सम्भावित 50 प ा डिस्पैंसरियों और 50 डिस्पैंसरियों एवं स्टाकमैन केन्द्रों को प ा हस्पतालों में तबदील किये जाने के काम के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त प ाओं की बीमारियों को समूल नश्अ करने का कार्यक्रम भी जारी रखा जाएगा। हरियाणा के मेवात क्षेत्र में 1981–82 के दौरान प ापालन संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के लिये 10.20 लाख रुपये का उपबंध किया गया है। इस उपबंध में 4 नई प ा डिस्पैंसरियां खोलने का, 4 डिस्पैंसरियों एवं स्टाकमैन केन्द्रों को प ा हस्पतालों में बदलने का, 8 नये स्टाकमैन केन्द्र स्थापित करने का और बछडा पालन, मुर्गीपालन और सुअर पालन आदि का कार्यक्रम भाामिल है।

सहकारी संस्थाओं ने किसानों को ऋण सुविधायें जुटाने, खेती की उपज के विक्रय में सहायता देने, सहकारी भंडारों के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई करने, फालतू दूध के लाभकारी प्रयोगों, कृशि आधारित प्रोसैंसिंग इकाइयों की स्थापना के कामों में प्रमुख भूमिका निभाई है। और वर्श 1981–82 के दौरान इन काम धंधों के लिए 6.28 करोड रुपये का उपबंध किया गया है। कृशि उत्पादन को बेचने और प्रोसैस करने की सुविधायें जुटाने के लिए हरियाणा राज्य सहाकरी सप्लाई एवं बिक्री संघ ने

डींग में कपास प्रोसैसिंग कम्पलैक्स की स्थापना करने के बाद 4 नए राइस भौलर लगाने की योजना बनाई है।

सार्वजनिक वितरण पद्धति अनिवार्य उपभोग्य वस्तुओं की बढती हुई कीमतों को रोकने के लिए सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा इसे और विस्तृत एवं सुदृड किया गया है ताकि वह ज्यादा से ज्यादा जनता वि ोश कर देहातों में रहने वाली जनता को लाभ पहुंचा सके जिससे उन्हें बढती हुई कीमतों से काफी हद राहत मिले। पहले जिक्र किया जा चुका है कि सरकार 2000 या इससे अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव में उचित दामों की दुकानें खोलने जा रही है और इस उद्दे य के लिये हरियाणा राज्य सहकारी खपतकार संघ को 1981–82 के दौरान 1. 40 करोड रुपये दिये जायेंगे। सरकार एक ऐसी म ीनरी को मजबूत बनाने का प्रयत्न कर रही है जो अनिवार्य वस्तुओं को लगातार 5213 उचित दामों की दुकानों के बाध्यम से उपलबध करा सके। काले बाजार और जमाखोरों की हरकतों का मुकाबला करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम दो उद्दे यों से आरम्भ किया गया है एक है रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करना और दूसरा है भीघ्र देहाती आर्थिक पुर्नव्यवस्था के लिए ग्रामीण आधार भूत संरचना खडी करना। इस उद्दे य के लिए सरकार ने 1981–82 की योजना में 3.18 करोड रुपये का उपबंध किया है और इसके लिए भारत सरकार से 3 करोड रुपये का 25 हजार

मीट्रिक टन अनाज और सामान की खरीद के लिये 1.50 करोड रुपया मिलने की संभावना है। सरकार गांव के स्तर की संस्थाओं को पोशित करना चाहती है और इस उद्दे य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पंचायत को पंचायत घरों के निर्माण कि लिए 20 हजार रुपये तक सहायता देने का प्रस्ताव है जहां कि ग्राम पंचायतें दिन प्रतिदिन की बैठकें कर सकती हैं। जमीन की लागत तथा अन्य खर्च का भार पंचायतों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

भौगोलिक परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाये रखना तथा उपजाऊ एवं कृशि योग्य भूमि की आर रेत के फैलाव को रोकना भी नितान्त आव यक है। इस उद्दे य को ध्यान में रखते हुए 1981–82 की वार्शिक योजना तें 3.50 करोड रुपये की व्यवस्था की गई हैं ताकि राज्य में भू सरंक्षण संबंधी कार्यवाही, वन साधनों में सुधार और जंगली जीवों की सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके। इस अवधि के दौरान वृक्ष लगाने के कार्यक्रम में 10680 हैक्टेयर भूमि पर तथा 11850 पंक्ति किलोमीटर पर वृक्ष लगाने का कार्यक्रम लगाने का कार्यक्रम बनाया गया है। इसके अतिरिक्त खेतों पर वन लगाने की स्कीम के अन्तर्गत 74.5 लाख पोधे और तीव्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक ब्लाक में एक लाख पोधे उगाये जायेंगे तथा फार्म की जमीनों पर लगोय जायेंगे। प्रत्येक जिले मेकं दो ब्लोकों में प्रत्येक बच्चे के लिए एक एक वृक्ष का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जायेगां

ये सभी स्कीमें श्रम साध्य हैं और इनसे कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार मुहैया होगा।

राज्य सरकार इस बात की आ ाा रखती है कि राज्य में उद्योग विकास के लिये और वि ोशतः ग्रामीण एवं छोटे उद्योगों के लिए बिजली कीद उपलभ्यता के साथ साथ जो अन्य सुविधायें प्रदान की जा रही हैं उनसे चालू वित्त वर्श की अपेक्षा वर्श 1981–82 में औद्योगिक उत्पादन की दर कहीं ऊंची होनी संभव होगी। इस वृद्धि को संभव बनाने के उद्दे य से अगले वर्श की योजना में 5.79 करोड रुपये का उपबंध किया गया है। मेवात क्षेत्र में तीन स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए भी कार्यवाही की जा रही है।

राज्य सरकार इस बात को समझती है। कि अधिक उत्पादन सुनि ि चत करने के लिए बेहतर औद्योगिक अनु ाासन और मजदूरों के विवादों के सम्बंध में मध्यस्थता और निर्णय के लिए कु ाल और समानता की नीति का अनुसरण करने की जरूरत हैं हमें आ ाा है कि राज्य के अंदर औद्योगिक संबंधों में जैसे कि इस वर्श नि चय से सुधार हुआ है वैसे ही वर्श 1981–82 के दौरान भी ये संबंध केवल ऐसे ही नहीं बल्कि इससे अधिक बेहतर होंगे। हम इस बात के लिए प्रयत्न ाील हैं कि उद्योगों के लिए प्र ि ाक्षित एवं हुनरमंद व्यक्ति उपलब्ध किय जाये और इस उद्दे य से मेवात क्षेत्र में तीन उद्योग प्र ि ाक्षण केन्द्र चालू किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन

सरकार विभिन्न व्यवसायों के लिए ि ाक्षु प्रि ाक्षण मुहैया करने की स्कीम बडे उत्साह के साथ चला रही है।

सडकें विकास की धमनियां हैं वश्र 1981–82 की वार्शिक योजना में 15 करोड रुपए की व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों की संचार व्यवस्था को सुदृढ करना है। आगामी वर्श के अंत तक ही मैदानों में 250 और पहाडी क्षेत्रों में 150 से कम की आबादी तक के लगभग सभी गांवों को लिंग सडकों से लाभन्वित किया जा सकेगा।

सडक संचार व्यवस्था में सुधार होने पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का जाल फैलाने की मांग को हरियाणा राज्य परिवहन के कार्य संचालन में इजाफा कर के पूरा किया जायेगा और राज्य परिवहन अपने बेडे में 200 नई बसों की वृद्धि के बाद अपनी पिछली वि ि ाश्अ कार गुजारी में चार चांद लगाने में सफल होगा। इस वृद्धि के बाद 1981–82 के अंत तक हरियाणा राज्य परिवहन के बेडे की कुल संख्या 2800 तक पहुंच जायेगी। वर्श के दौरान 9 आधुनिक बस अड्डे तथा 100 बस प्रतीक्षालय बनाने का काम आरम्भ किया जायेगा। इन सब काम धंधों के निमित 1981–82 के लिए 10 करोड रुपए का उपबंध कर दिया गया है।

हरियाणा पर्यटक विभाग और निगम का 1.25 करोड रुपए का योजना आबंटन है वे इस आबंटन से अपनी ऊंचे स्तर की कार्य कु ालता और दक्षता को न केवल बनाए रखते हुए

बल्कि उसमें और सुधार लाते हुए पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए समान रूप से सुविधाएं प्रदाने करने का प्रस्ताव रखते हैं।

हमारा भविश्य हमारे बच्चों की ि ाक्षा दीक्षा पर निर्भर करता है। अतः सामान्य ि ाक्षा, कला और संस्कृति के लिये 9.90 करोड रुपए और तकनीकी ि ाक्षा के लिए 52 लाख रुपए के योजनागत परिव्यय का उपबंध किया गया है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर ि ाक्षा में सुधार लाने के उद्दे य से हमने इस वर्श प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों का दर्जा बढाया तथा गैर सरकारी स्कूलों एवं कालेजों को सरकारी व्यवस्था में लिया। 1981–82 के दौरान भी इस कार्यक्रम पर बल दिया जाता रहेगां। गैर सरकारी महाविद्यालयों के प्रबंधकों तथा स्टाफ की एक लंबे अरसे से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने आगामी वर्श से इन संस्थाओं के वर्तमान 75 प्रति ात घाटे के स्थान पर 95 प्रति ात घाटा पूरा करने के लिये अनुदान देने का नि चय किया है। स्कूल जाने वाले बच्चों को और अधिक सुविधायें प्रदान करने की जरूरत को समझते हुए, चालू वित्त वर्श के दौरान सभी भौक्षणिक ब्लाकों में दोपहर के भोजन का कार्यक्रम चालू कर दिया गया था। हरियाणा राज्य यौग्यता छात्रवृति की स्कीम के लिए माता पिता की वार्शिक आय की सीमा को 6000 रुपए से बढाकर 10000 रुपये प्रति वर्श कर दिया गया है। हम अपने नौजवानों में नेतृत्व के गुण और अनु ाासन की भावना पैदा करने के लिए खेलों के महत्व को

भी मान्यता प्रदान करते हैं चालू वित्त वर्श से एक स्पोर्टस होस्टल जारी हो चुका है और इस विभाग के लिए योजनागत परिव्यय में 60 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी गई है ताकि वे अपने कार्यक्रम काचे जारी रख सके। अधिक कोचिंग सुविधायें प्रदान करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

राज्य सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रक्षा की सुविधाओं को बढाने के लिए और वि ोशकर देहाती एवं पिछले क्षेत्रों में इन सुविधओं के विस्तार के लिए अत्यकिधक प्रयत्न किये हैं और वश्र 1980–81 के दौरान सात नये सहायक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं तथा सोहना, पलवल, जगाधरी और चौटाला में हस्पतालों के नये भवनों को चालू किया गया है। इसके अतिरिक्त 20 नई आयुर्वैदिक डिस्पैंसरियां खोलने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है तथा भिवानी के सिविल हस्पताल में आयुर्वेदिक विंग की स्थापना की गई है। आबादी वृद्धि की ऊंची दर से राज्य की अर्थ व्यवस्था की वृद्धि दर कहीं बेकार न हो जाये। इसलिये राज्य सरकार राश्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक लागू कर रही है और उद्दे य यह है कि जन्म दर को मार्च 1983 तक 30 प्रति हजार तक लाया जा सके। इन उद्दे यों की प्राप्ति के लिए वश्र 1981782 की वार्शिक योजना में स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद के लिये 7.50 करोड रुपये की व्यवस्था की गई हैं हम निवारक स्वास्थ्य सेवा को भी उचित महत्व दे रहे हैं और हमारी कोि ा ों हैं कि परिस्थितियां ऐसी पैदा की जाएं कि राज्य में बीमारी की

सम्भावना कम रहे। इसके दृश्टिगत जल सप्लाई और खास तौर पर ग्रामीण जल सप्लाई तथा मल निकास की स्कीमों को प्राथमिकता दी जा रही है। 1981–82 में राज्य के 210 गांवों को जल सप्लाई की सुविधा प्रदान के करने के लिए 9.70 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अतिरिक्त देहाती क्षेत्र में पेय जल सुविधा प्रदान करने की केन्द्र चालित स्कीमें भी होंगी। राज्य की जल सप्लाई परियोजनाओं के लिए वि व बैंक से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। राज्य सरकार भाहरी जल सप्लाई और मल निकास स्कीमों पर भी वर्श 1981–82 के दौरान 2.27 करोड रुपया खर्च करने का विचार रखती है।

सरकार अपने नागरिकों के लिए बेहतर आवास सुविधायें जुटाने के लिए गम्भीरता से सोच रही है। आवास बोर्ड अपने कार्यक्षेत्र को बढाने का विचार कर रहा है तथा इस वर्श मुर्हया किये जाने वाले सम्भावित 4000 मकानों के अतिरिक्त यह वर्श 1981–82 के अंत तक 5000 नये मकान मुहैया करने की आ ाा करता है और इसके इलावा पांच हजार मकानों के निम्रण का कार्य का आरम्भ करने का विचार रखता है। इनमें से 75 प्रति ात मकान समाज के कमजोर वर्ग के लिए होंगे। हम इस बात के प्रति जागरूक हैं कि लोगों को, आज खास तौर से देहाती लोगों को सस्ते मकान मुहैया किए जाएं तथा इस उद्दे यों की प्राप्ति के लिए वर्श 1981–82 के दौरान 5.60 करोड रुपये की व्यवस्था कर दी गई हैं

गरीब लोगों की रिहाय ा वाली झुग्गी झोंपडियों की ओर वि ोश ध्यान दिया जा रहा है। राज्य की कुछ भाहरी नई कालोनियों में ऐसे निवासियों को एक कमरे वाले मकानों के लिये छोठे प्लाट दिलवाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जुलाई 1981 में सूर्यग्रहण आ रहा है और कुरुक्षेत्र नगर को इस अवसर के निमित तैयार करने के लिए तथा ब्रह्मसरोवर के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए ताकि यात्रियों को सुविधा रहे, राज्य सरकार ने इस वर्श कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को 67 लाख रुपये का सहायतनुदान दिया है।

सरकार बेरोजगारी की समस्या को जो कि अधिकतर कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अभि ााप बनी हुई है। हल करने के लिए वचनबद्ध है। कुल रजिस्ट्रे ान के मुकाबले नौकरी प्राप्त करने वालों की संख्या 16.4 प्रति ात थी जबकि अखिल भारतीय प्रति ातता 9.4 रही। देहाती नौजवानों को अधिक नौकरियां दिलाने के लिए राज्य के 6 और स्थानों पर रजिस्ट्रे ान सुविधायें मुहैया की गई हैं। सभी अनुसूचित रोजगारों में अकु ाल मजदूरों की मजदूरी की दर बढाकर 253.50 रुपये मासिक कर दी गई है।

हरियाणा सरकार हरिजनों, तपरीवास और विमुक्त जातियों सहित पिछडे वर्गों के उत्थान को अत्यकिधक प्राथमिकता प्रदान कर रही है। राज्य में 26 मान्यता प्राप्त तपरीवासियों और विमुक्त जातियों में से 11 जातियां पहले से ही अनुसूचित जातियों में हैं और 6 जातियां पिछडे वर्गों की घोशित की हुई हैं। भोश 9

अर्थात तगों, बादियों, बनजारों, मल्लाहों, ारगीरों, हेडियों, भाटों, धीवरों और मीनाओं को पिछडे वर्गों में घोशित करनें का प्रस्ताव है पिछडे वर्गों के निगम और हरिजन कल्याण निगम को प्रदान की गई निधियों में से 30 लाख रुपया वि ोशतया तपरीवास और विमुक्त जातियों के लाभ की योजनाओं पर खर्च करने के लिये नियत करने का सुझाव है और उचित परिवीक्षण पद्धति के माध्यम से यह सुनि ि चत कर लिये जाने का विचार है कि उन्हें पर्याप्त वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायकता प्राप्त हो रही हैं गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाला सबसे अधिक अकेला समुदाय सामान्यतः हरिजन जातियों में से है। इस समुदाय के पिछडेपन को दूर करने के लिए वि ोश महत्व को महसूस करते हुए सरकार ने हरिजनों के विकास के लिये वि ोश कार्यक्रम तैयार कियें हैं जिनका मुख्य उद्दे य यह है। कि इस समय गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले हरिजन परिवारों में से 50 प्रति ात परिवारों को छठी योजना की अवधि के दौरान गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाये। इस उद्दे य को ध्यान में रखते हुए वर्श 1981–82 की वार्शिक योजना के कुल 290 करोड रुपये के परिव्यय में से हरिजन कल्याण की वि ोश स्कीमों के लिये 35.57 करोड रुपये का उपबंध किया गया है। वर्श 1981–82 के दौरान 1.80 करोड रुपये के उपबंध से लडके लडकियों के होस्टल और महिला प्र ि ाक्षण एवं उत्पादन केंद्र खोलने, हरिजन बस्तियों के परिवे ा में सुधार लाने तथा हरिजन बस्तियों को पीने का पानी सप्लाई करने और प ा खरीदने के लिए सहायतनुदान देने आदि

की नई स्कीमें चालू की जाएंगी। हरियाणा हरिजन कल्याण निगम द्वारा 10000 परिवारों को वर्श 1981–82 के दौरान अपना उपक्रम चालू करने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है और राज्य सरकार इस निगम की हिस्सा पूंजी के लिये 50 लाख रुपया प्रदान करेगी। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि वर्श 1981–82 से हरिजन लडकों को छात्रवृति देने के लिऐ आमदनी की सीमा 4200 रुपये प्रतिवर्श से बढाकर 6000 रुपये प्रति वश्र कर दी जाये। (थम्पिंग)

निराश्रित स्त्रियों, बच्चों, बूढों, निर्बलों तथा अपाहिज लोगों के कल्याण के लिये बहुत सी स्कीमें तैयार करके अमल में लाई गई हैं। इन स्कीमों के लिए वर्श 1981–82 के दौरान 80 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है और पोशण कार्यक्रम के लिये 80 लाख रुपये की अतिरिक्त रा ि ा का उपबंध किया गया है। वश्र 1981–82 के दौरान गहन ि ा ु विकास के तीन नये प्राजैक्ट चालू करना प्रस्तावित है जबकि इस वर्श इसी प्रकार के दो प्रोजैक्ट आरम्भर किये गये थे। यद्यपि विकलांग लोग कभी भी हमारे ध्यान से ओझल नहीं हुए तथापि वर्श 1981 वि व विकलांग व्यक्ति वर्श घोशित किया गया है। अतः इस वर्श भाारीरिक दृश्टि से विकलांग लोग हमारे वि ोश ध्यान और अपनी वित्तीय एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिये सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। राज्य भर के विकलांग लोगों का सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया गया है जिससे उनकी समस्या का अनुमान लग सकेगा और

मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षत में राज्य स्तीरय समिति भी गठित कर दी गई हैं राई में नेत्रहीन लडकियों कें लिये भवन का निम्रण आरम्भ करके वि व विकलांग व्यक्ति वर्श का उदघाटन 2 जनवरी 1981 को किया गया। इसके इलावा सरकारी नौकरी में कुछ रिक्त स्थान नेत्रहीनों और विकलांग लोगों के लिये आरक्षित कर दिये गये हैं। विभिन्न रैडक्रास समितियों की सहायता से रोहतक में मंदतमना बच्चों के लिए और राई में नेत्रहीन लडकियों के लिये सदन तथा पानीपत में नेत्रहीन लडकों के लिये इंजीनियरिंग सामान का प्रि ाक्षण केन्द्र और अम्बाला में आंि ाक रूप से विकलांग लोगों के लिये नई परियोजनायें चालू की जा चुकी हैं। (थम्पिंग) जिनके लिये भारत सरकार से काफी सहायता प्राप्त होने की संभावना है।

सरकार सम्पत्ति के समान वितरण की समस्या की ओर जागरूक है और इस उद्दे य को ध्यान में रखते हुये राज्य के सरप्लस क्षेत्र को मुजारों और भूमिहीन मजदूरों आदि पात्र व्यक्तियों में बांटा जा रहा है। हमें आ ाा है कि राज्य की सारी सरप्लस भूमि मार्च 1981 के अंत तक बांट दी जायेंगी।

चौधरी गंगा रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर।

Mr. Speaker: Under what rule ?

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, हाउस के अंदर एक सी0आई0डी0 आफिसर खडा हुआ है और मुझे घूर घूर कर देख

रहा है। यह डी0एस0पी0, सी0आई0डी0 हैं आप चाहें तो इंक्वायरी करवा सकते हैं। (ाोर)

Mr. Speaker: There can not be any policeman in the House. If there is anybody in the House by mistake, he must not be here. मुझे बताया गया है कि हाउस के अंदर कोई पुलिस आफिसर नहीं है।

चौधरी गंगा रामः आप इंक्वायरी करवा सकते हैं। अभी भाग कर गया है। डी0एस0पी0, सी0आई0डी0 को मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे लिये यह पार्टिकुलरली आया है। He knows me. यह डी0एस0पी0 ऊपर सामने खडा हुआ था और मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मेरे विरूद्ध यहां पर कोई साजि ा रची जा रही है। हो सकता है कि मुझे सदन से बाहर निकलने पर गिरफ्तार किया जाये। पुलिस का कोई भी आदमी हाउस के अंदर होना ठीक नहीं है।

Mr. Speaker: All right. Please sit down. It has been brought to my notice.

आवाजें: यह इतना इम्पोर्टैंट आदमी नहीं है कि इसे गिरफ्तार किया जाये।

चौधरी गंगा रामः अगर इम्पोर्टैंट नहीं होते तो .....

..

श्री अध्यक्षः यह रिकार्ड न किया जाये। वित्त मंत्री जी अपना भाशण जारी रखें।

चौधरी खुर ीद अहमदः मेवात विकास बोर्ड के कार्यक्रमों का मैंने पहले भी जिक्र किया था। कृशि, प ुपालन, औद्योगिक प्र ि ाक्षण, वन, मत्स्यपालन और सिंचाई विभागों की विकास स्कीमों के अतिरिक्त उद्योग विभाग इस इलाके में उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजीनिवे ा पर 15 प्रति ात सहायतानुदान देता है तथा बीज रा ि ा और ऋणों का प्रबंध करवाता है। सरकार इस क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों की रफ्तार बनाये रखना चाहती है और इस उद्दे य से अगले वर्श की योजना में दो करोड रुपये का उपबंध किया है ताकि यह इलाका जल्दी ही राज्य के अन्य इलाकों के बराबर आ सके।

राज्य सरकार व्यापार और उद्योग की आव यकताओं और जरूरतों के प्रति जागृत रही है। बिक्री कर प्रक्रिया एवं संरचना का अध्ययन करने और इसे तर्कसंगत बनाने के लिये गठित की गई कर संरचना पुनरीक्षण समिति ने बहुत सी मांगों और सुझावों पर विचार किया है तथा सरकार ने समिति की कुछ सिफारि ाों को कार्यान्वित भी किया है यद्यपि समिति की आखिरी रिपोर्ट आनी है। रक्षा कार्मिकों, निर्माताओं और दूसरों को कई प्रकार की रियायतें दी गई हैं

पिछले पैरों से पता चलता है कि वर्श 1981–82 के दौरान योजना उपबंध वर्श 1980–81 के 253.78 करोड रुपये के प्रावधान की अपेक्षा 36.22 करोड रुपये अधिक हैं लेकिन वर्श 1981–82 में योजनेतर राजस्व खर्च वर्श 1980–81 के सं ाोधित अनुमानों में इस मद के लिये किये गये उपबध से 70 लाख रुपये कम हैं। वर्श 1980–81 के सं ाोधित अनुमानों में योजनेतर राजस्व खर्च के लिये 331.41 करोड रुपये का उपबंध किया गया है। इस कमी का कारण हयह है कि चालू वर्श के दौरान सं ाोतिध अनुमानों में सरकारी कर्मचारियों को वेतन सं ाोधन के कारण देय बकायों की अदायगी के लिये काफी उपबंध करना पडा। वर्श 1981–82 के दौरान अधिकां ा मुख्य भीशार्ों के अंतर्गत अधिक खर्च का उपबंध केवल प्रसासकीय खर्च और वेतनमानों आदि में होने वाली सामान्य वृद्धि के कारण किया गया है। योजनेतर राजस्व खच्र में उल्लेखनीय वृद्धि केवल परिवहन विभाग के उपबंधों में (5.77 करोड रुपये) हुई है जो बसों की संख्या में वृद्धि और महंगाई के कारण परिवहन सेवा के परिचालन व्यय में वृद्धि के कारण हुई है। सिंचाई विभाग के उपबध में की गई वृद्धि (5.41 करोड रुपये) प्रति प्रविि ट (कान्टरा ऐन्टरी) के रूप में हुई है क्योंकि अधिक पूंजी निवे ा के कारण राजस्व पर लगने वाला अधिक बयाज राज्य सरकार की आय में गिना जाता है। ि ाक्षा में 2.80 करोड रुपयो के अधिक उपबंध से पता चलता है कि सरकार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की आव यक मांगों की पूर्ति के लिए कितनी आतुर है। राज्य सरकार के ब्याज की अदायगियां भी 2.54 करोड

रुपये बढ गई हैं। फिर भी कई एक मुख्य भीर्शों के अन्तर्गत योजनेतर राजस्व खर्च कम कर दिया गया है और इनमें से सबसे अधिक उल्लेखनीय है प्राकृतिक प्रकोप के कारण राहत के खर्च का उपबंध जो 9.14 करोड रुपये कम किया गया है। इस वर्श राज्य सरकार को अधिक रकम का उपबंध इसलिये करना पडा ताकि वह प्राकृतिक प्रकोप से पीडित किसानों को सहायता प्रदान कर सके, जबकि वर्श 1981–82 के दौरान सातवें वित्त आयोग की सिफारि ाों के अनुसार इस मद के लिये 1.47 करोड रुपये का ही उपबंध किया गया है और हमें आ ाा है कि इस वर्श से प्रकृति हमारे ऊपर कृपा करेगी। वर्श 1981–82 के बजट अनुमानों में सामुदायिक विकास के खर्च के उपबंधों में 11.67 करोड रुपये की कमी हो गई है क्योंकि राश्ट्रीय देहाती रोजगार का कार्यक्रम योजनेतर पक्ष से योजना पक्ष को आन्तरित कर दिया गया है।

वर्श 1981–82 के दौरान राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों के 518.24 करोड रुपये तक पहुंच जाने की संभावना है जबकि वर्श 1980–81 के सं ाोधित अनुमानों के अनुसार इसके 459.07 करोड रुपये होने की संभावना है और वर्श 1979–80 में यह 402.12 करोड रुपये थी। इस प्रकार प्राप्तियों में वर्श 1980–81 की अपेक्षा 12.89 प्रति ात वृद्धि हुई है। केन्द्रीय करों में हिस्सा 5.72 करोड रुपये बढा जबकि राज्य करों में और नौन टैक्स राजस्व में क्रम ाः 35.85 करोड रुपये और 3.93 करोड रुपये की वृद्धि हुई है। राज्य के करों में सबसे अधिक उल्लेखनीय

वृद्धि 15.90 करोड रुपये बिक्री कर में है जो कि वर्श 1981–82 के दौरान कृशि और औद्योगिक उत्पादन में सुधार होने कें कारण तथा बेहतर व्यवस्था के कारण है। इस वर्श बसों के किराये में हुई वृद्धि के कारण यात्री और सामान के करौं की प्राप्तियां 5.64 करोड रुपये अधिक होगी। बिजली भाुल्क से भी वर्श 1981–82 के दौरान 4.39 करोड रुपये अधिक वसूली होने की संभावना है क्योंकि बिजली बोर्ड को आ ाा है कि अगले वर्श ज्यादा बिजली पैदा होगी और इसकी बिक्री भी ज्यादा होगी। इसके अतिरिक्त बिजली की दरों में सं ाोधन भी हुआ है। वर्श 1981–82 के दौरान भू राजस्व, टिकट और रजिस्ट्री, राज्य आबकारी और वाहन करों की वसूलियां भी वर्श 1980–81 की प्रत्याि ात वसूलियां से क्रम ाः 1.64 करोड रुपये, 1.57 करोड रुपये, 4.00 करोड रुपये और 1.24 करोड रुपये अधिक होंगी। वर्श 1981–82 में नौन टैक्स राजस्व में भी 23.93 करोड की वृद्धि का पता चलता है। इसके मुख्य रूप से ब्याज की 12.35 करोड रुपये की प्रत्याि ात अधिक प्राप्तियों के कारण हैं।

निवल बजट लेन देन

अब तक खर्च और प्राप्तियों की हुई चर्चा के परिणामस्वरूप बजट अनुमानों की स्थिति उभर कर सामने आती है :–

(रुपये करोड़ों में)

संघटक	बजट अनुमान 1980–81	सं ाोधित अनुमान 1980–81	बजट अनुमान 1981–82
अथ भोश	(–) 19.32	(–)12.02	(–)37.84
राजस्व लेखे:			
प्राप्तियां	433.33	459.07	518.24
खर्च	365.39	410.05	434.35
अधि ाेश	(+)67.94	(+)49.02	(+)83.89
घाटा	–	–	–
पूंजीगत व्यय			
निवल	99.67	105.87	119.06
लोक ऋण			

लिया गया ऋण पुनः अदायगी निवल	230.36 193.21 (+)37.15	316.43 256.55 (+)59.88	335.06 296.08 (+)38.96
कर्जे और पे ागियां पे ागियां वसूलियां निवल	61.22 13.45 (–)47.77	80.02 11.96 (–)68.06	71.60 24.75 (–)46.85
अन्तर्राज्यीय भुगतान			
आकस्मिक निधि निवल		(+)1.07	
अनिधिक ऋण (निवल)	(+) 14.95	(+)22.00	(+)17.03
जमा और पे ागियां (निवल)	(+)13.78	(+)15.14	(+)0.80

प्रेशण (निरवल)		(+)1.00	(+)0.80
वर्श का इति ोश	(–)32.94	(–)37.84	(–)49.20

इससे पता चलता है कि चालू वित्त वर्श 37.84 करोड रुपये के घाटे के साथ समाप्त होगा। पिछले वर्श प्रस्तुत किये गये अनुमानों के साथ तुलना करने से पता चलता है कि चालू वर्श का इति ोश प्रत्याि ात इति ोश से बहुत कम है। वर्श 1980–81 के बजट अनुमान करते समय यह अनुमान था कि यह वर्श 32.94 करोड रुपये के घाटे के साथ समाप्त होगा और जिसके वेतन आयोग की सिफारि ों पर किए गए खर्च के कारण लगभग 15 करोड रुपये तक बढ जाने की संभावना थी। इस प्रकार वर्श 1980–81 के अंत में कुल 47.94 करोड 3पये के घाटे की संभावना थी। (ोम भोम) तथापि वर्श के दौरान सरकार ने योजनागत परिव्यय में 13.28 करोड रुपये की वृद्धि की और प्राकृतिक आपदाओं का ि ाकार होने वाले लोगों को राहत मुर्हया करने पर 10.98 करोड रुपये का अतिरिक्त व्यय किया तथा वेतन आयोग की सिफारि ों लागू करने के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की चार किस्तें भी दी, जिन पर 11.28 करोड रुपया खर्च हुआ और बावजूद इस बात के कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्राप्तियां भी कम हुई हैं। वर्श अपेक्षाकृत कम घाटे से

समाप्त हो रहा है। इसका कारण यह है कि प्राप्तियों में वृद्धि हुई है और कर वसूली की दि ाा में राज्य सरकार की कारगुजारी बेहतर रहीं

नफी 37.84 करोड रुपये के अथ ोश को लेखे में भाामिल करने के बाद वर्श 1981–82 के अंत में नफी 49.29 करोड रुपये का इति ोश होगा। (ोम भोम) इस वर्श के लेन देन खाते में 11.45 करोड रुपये का घाटा होगा। इस पर विचार करते हुए हमें यह बात नहीं भुलानी चाहिये कि हमने योजनेतर राजस्व खर्च में पर्याप्त कमी कर दी है और इति ोश की वृद्धि का कारण यह है कि वर्श 1981–82 के योजनागत परिव्ययों मैं वृद्धि हुई है जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण वास्तविक संवृद्धि प्राप्त करने के लिए अनिवार्य थी।

उपसंहार

हमने अपने सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में सं ाोधन और महंगाई भत्ते की वृद्धि के रूप में उन्हें दी गई उदार और वित्तीय दृश्टिकोण से पर्याप्त राहत के बारे में विचार किया है। भविश्य में रिटायर होने वालों को और मौजूदा पैं ान पाने वालों के सेवा निवृति लाभों में पर्याप्त सुधार कर दिया गया है। सभी पैं ान पाने वाले कर्मचारी वर्ग ने हमारी पैं ान भार्तो की प्र ांसाच की है। मैं प्रत्येक वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को वि वास दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार वर्तमान कठिन

परिस्थितियों में उनकी हालत के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखेगी। इसके परिणामस्वरूप मैं इस असवर पर महंगाई भत्ते की एक और किस्त की घोशणा करता हूं। (थम्पिंग) जो कि अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक के 376 बिन्दु पर पहुंचने के फलस्रूप 1 सितम्बर 1980 से देय हुई है। इस किस्त की 28 फरवरी 1981 तक की रा ि ा उनकी भविश्य निधियों के खातों में जमा करके अदा की जायेगी और इसके बाद नकदी के रूप में दी जायेगी। अपने साधनों और कर्मचारियों के उत्पादन के दृश्टिगत हम भविश्य में भी इसी प्रकार की उदार नीति के अनुसरण का विचार रखते हैं। तथापि यह मानना होगा कि प्र ाासन चलाने का मूल उद्दे य राज्य का विकास करना है और लोगों को ऐसे आव यक तत्व जुटाना है जो कि उनकी आर्थिक व्यवस्था को खु ाहाल बनायें और उनके जीवन में सम्पन्नता लाएं और यह कर दाताओं को अपनी रा ि ा से ही किया जाता है। सरकार का दृढ विचार है कि लोगों के प्रति उसका यह कर्त्तव्य है कि वह उन्हें ऐसा प्र ाासन दें जो कि कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक कार्यकु ाल हो। चूंकि सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही इस उद्दे य की प्राप्ति हो सकती है। इसलिये यह आव यक है कि वह स्वयं भी इस नीति को पूर्ण रूप से अपनायें। हम उनसे अधिक से अधिक काम की आ ाा रखते हैं। हमारा प्रयत्न होगा कि हम कर्मचारियों की संख्या को कम से कम करके तथा स्टाफ के नार्म में सं ाोधन कर के वेतन आदि पर होने वाले व्यय को लगभग 10 प्रति ात घटा दें। हमारा यह इरादा नहीं है कि हम उन लोगों को नौकरी से

हटायें जो कि अब नौकरी में हैं बल्कि हमारा विचार है कि हम युक्ति युक्त तरीके से इस बात का निरीक्षण करें कि स्टाफ की कितनी आव यकता है और इस बीच में नई भर्ती पर मौजूदा प्रतिबंध को दृढतापूर्वक लागू करें। इसमें सफल होने पर हमें आ ाा है कि खर्च के मौजूदा स्तर में 12 करोड रुपये की बचत हो सकैगी।

यही बात सामान्य रूप से प्र ाासकीय खर्च के सबंध में भी सही होगी। हमारा ख्याल है कि हम अनुत्पादक प्र ाासकीय खर्च की विभिन्न मदों वस्तु सूची का स्तर, उसके प्रयोग एवं निपटान के सबंध में चालू मानों और परिपाटियों का उचित ढंग से पुनरीक्षण करें ताकि यथासम्भव बचत हो पाये। हमारी सफलता का कुछ हद तक अंदाजा हमारे योजनेतर खर्च की वृद्धि के तुलनात्मक अध्ययन से लग सकता है जो कि मैं पहले पे ा कर चुका हूं। हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगें इस तरह 1981–82 में 3 करोड रुपये की बचत सम्भव हो सकेगी।

सार्वजनिक उपक्रमों की धूमिल कारगुजारी के बारे में दे ा के सभी भागों में चिनता हो रही है। सारा राश्ट्र इस बात पर एकमत है कि उनकी इस गिरती हुई हालत को संभाला जाये और जहां तक संभव हो सके प्र ाासन के आधुनिक तरीकों को प्रयोग करके उनकी लागत दक्षता में सुधार लाया जाये, जिजसे वह आत्मनिर्भर हो सकें जैसा कि और जगहों पर भी हुआ है, यहां भी राज्य बिजली बोर्ड के आधारभूत साधनों में निरन्तर गिरावट

आयी हैं। यद्यपि इसने लाइन की हानियों को कम करके तथा कार्यकु ालता बनाये रख कर सराहनीय काम किया है लेकिन बढती हुई कीमतें, कृशि क्षेत्र के लिये निर्धारित रियायती दरों, पन तथा ताप बिजली के संमिश्रण का प्रतिकृल अनुपात तथा देहाती क्षेत्र में बिजली बडे पैमाने पर पहुंचाने के लिये बहुत विस्तृत लाइनों का जाल कुछ ऐसे कारण हैं जिससे बोर्ड को लगातार नुक्सान हुआ है। हम बहुत भीघ्र ही एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने जास रहे हैं जो कि इन समस्याओं को अध्ययन करें ताकि कार्य संचालन के उन्नत तरीकों को प्रयोग में लाकर हर प्रकार से संभव बचत की जा सके। इसमें जो कुछ भी सुधार लाया जा सकेगा, उससे राज्य के बजट को राहत मिलेगी क्योंकि उसका बोर्ड को ऋण देने का दायित्व कम हो जायेगा। इसी प्रकार हम राज्य के अन्य प्रमुख उपक्रमों यथा हरियाणा राज्य परिवहन के कार्य संचालन एवं विस्तृत कार्य क्षेत्र के फलस्वरूप ट्रैफिक घनत्व की न्यूनता के होते हुए भी उन की वित्तीय कारगुजारी में सुधार लाया जा सके। हमारा लक्ष्य यह होगा कि हम इन तरीकों से कुल पांच करोड रुपये की लागत दक्षता प्राप्त कर सकें

यद्यपि वर्श 1981–82 में लोगों को अतिरिक्त करों के भार से हम मुक्त रखना चाहते हैं लेकिन यह भी स्पश्अ है कि हम विकास की रफ्तार को तेज करने में तभी सफल हो सकते हैं जबकि हम उद्दे य के लिये अनिवार्य वित्तीय साधनों को जुटा लें। नहीं तो पूरे न किये गये घाटे सें मुद्रास्फीति को बल मिलने की

संभावना के कारण विकास का उद्दे य ही समाप्त हो जाता है। हमारा वि वास है कि लोगों के पास इस बात के लिये काफी गुंजाइ ा है कि वे सरकार के पूर्व निर्दिश्ट प्रयत्नों में अपना भी योगदान बचत की पहले से विद्यमान विभिन्न आकर्शक स्कीमों में खुल दिल से पेसा जमा करवा कर दें। लम्बी अवधि के "बचत सर्टीफिकेटों" तथा डाकखानों के बचत बैंकों और "पेरोल" बचत स्कीमों जिनसे जनता भलीभांति परिचित हैं, के इलावा व्यक्तिगत निवे ाकर्त्ता के यि "ग्रामीण ऋण पत्र" स्कीम भी है, जिस पर 12 प्रति ात की दर पर ब्याजा मिलता है और यह दस साल में परिपक्व होती हैं इसके इलावा हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की नियताबधिक जमा स्कीम है जिसका ब्याज वाणिज्यिक बैंकों के समान है। राज्य की लगभग 2500 करोड रुपये की आय पर केवल आधे प्रति ात की अतिरिक्त बचत से 12 करोड रुपये से अधिक की रकम प्राप्त हो सकेगी। यदि इसे दूसरे ढंग से देखें तो 10 रुपये प्रति व्यक्ति की बचत से यह वसूली संभव हो सकेगी। जहां कुछ ऐसे परिवार भी होंगे जो कि थोडे से प्रयत्न से महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। इसमें अपनी बचत की आदत को सुदृढ बनाना होगा। प्रत्येक सामुदायिक विकास ब्लौक से कम से कम 10 लाख रुपये की अतिरिक्त बचत प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन प्रधान कार्यक्रम के माध्यम से पूर्ण स्वेच्छा के आधार पर, यह लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा।

16.00 बजे।

प्रस्तावित उपाय यानि स्टाफ में कमी, सरकारी विभागों और प्रमुख उपक्रमों में बचत कार्यक्रम और प्रस्तावित बचत अभियान वर्श 1981–82 के अंत के घाटे के लगभ 30 करोड रुपये को पूरा करेंगे। भोश घाटा यदि पूरी तरह से नहीं तो काफी सीमा तक उस केन्द्रीय कानून के बनने के बाद पूरा हो सकेगा जिससे कनसाइनमैंट टैक्स लगेगा। माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है कि फरीदाबादी, बहादुरगढ, जगाधरी आदि प्रमुख औद्योगिक नगरों से प्रति वर्श लगभग 200 करोड रुपये का उत्पादित माल मनसाइनमैंट के रूप में राज्य से बाहर जाता है जिस पर वर्तमान नियमों के अनुसार राज्य की किसी बिक्री कर की आय नहीं होती। यह महत्त्वपूर्ण विशय पर राश्ट्रीय विकास परि ाद की बैठक में भी विस्तार से चर्चा हुई थी। हमें आ वासन प्राप्त हुआ है कि केन्द्रीय सरकार भीघ्र ही इस संबंध में कानून बनाने जा रही है जिससे कि ऐसा कर स्थानांतरित माल पर लगाना सम्भव होगा। इससे होने वाली आय तथा प्राप्तियों में अन्य वृद्धियां, जिसकी पूर्ण संरचना है, से भोश घाटा आसानी से पूरा हो जायेगा।

अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व मैं अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहूंगा कि इस राज्य के लागे इस सदन में बैठे हुये हम लोग जो कि उन के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और वास्तव में एक मामूली मजदूर से लेकर एक बडे से बडे कार्यकर्त्ता तक सभी लोग जो कि इस राज्य से किसी प्रकार का संबंध रखते हैं, नये वित्त वर्श के आरम्भ में प्रगति और खु ाहाली तथा समानता एवं

कल्याण के क्षितिज करे विस्तृत करने के संकल्प के प्रति सामूहिक समर्पण की भावना रखेंगे।

अब मेरे लिये वित्त विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों, महालेखापाल, हरियाणा और उसके सहयोगियों तथा चण्डीगढ़ प्र ाासन के मुद्रणालय के प्रति आभार प्रकट करना ही भोश रह गया है कि उन्होंने इतने थोडे समय में बजट तैयार करने में हमें बहुमूल्य सहायता प्रदान की है।

श्रीमान, मैं इन भाब्दों के साथ सदन के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ 1981–82 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हू।

जय हिन्द!

श्री अध्यक्षः चौधरी गंगा राम ने प्वाएंट उठाया था कि कोई पुलिस वाला उन्हें देख रहा था। वह मैंने चैक किया है। कोई भी पुलिस वाला नहीं था।

The House stands adjorned till 9.30 a.m. tomorrow.

***16.05 बजे।**

The Sabha then *adjorned till 9.30 a.m. on Tuesday, the 17th March, 1981.)